दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/23 (J-A)–M–GSM (P-III)-2302

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Ishwar Lal Gurjar

Medium (English/Hindi): Hindi

Center & Date: Delhi, 27-06-2022

Mobile Number: Hin-

Reg. Number:

UPSC Roll No. *(If allotted)*: 1136207

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

1. "अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन, संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस है।" प्रमाणित कीजिये। (150 शब्द) 10

"Repromulgation of Ordinance is a fraud on the constitution and a subversion of democratic legislative process". Substantiate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संविधान के अनुच्छेद - 123 में राष्ट्रपति एवं 'अनु-च्छेद - 213' में राज्यपाल को सदन के सत्र में न होने पर अध्यादेश प्रख्यापन की अस्थाई विधिक शक्ति प्रदान की गई है।

कार्यपालिका की यह विधायी शक्ति सीमित व अस्थाई है लेकिन इसका बारम्बार प्रयोग विधायिका की शक्तियों को 'बाईपास' करने जैसा है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद (1987) में असंवैधानिक माना।

अध्यादेश संबंधी संवैधानिक प्रावधान :—

→ (A) राष्ट्रपति एवं राज्यपाल मंत्रि परिषद की सलाह पर सदन के सत्र में न होने पर अध्यादेश प्रख्यापन कर सकते हैं जो विधि के समान मान्य होगा।

→ (B) सत्र आरम्भ होने पर 6 सप्ताह के भीतर इसे सदन से पारित करना होगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

(1) अध्यादेश की बारम्बारता संबंधी प्रावधान पर संविधान मौन है इसी का लाभ उठाकर कार्यपालिका द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है जैसे — बिहार में सरकार द्वारा एक ही अध्यादेश को 250+ बार पुन: प्रख्यापन

पुन: प्रख्यापन संविधान के साथ छल

→ (A) विधि निर्माण विधायिका का संवैधानिक कार्य है कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण असंवैधानिक

(B) कार्यपालिका द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन 'विधि का शासन' के खिलाफ

(आगे) → कृष्णा कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अध्यादेश के पुन: प्रख्यापन को असंवैधानिक माना और इस शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती

→ विधायिका में चर्चा की संस्कृति को बढ़ाना और जनता में विधिक जागरूकता द्वारा प्रहरी का कार्य किया जा सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

2. "मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक और वांछनीय दोनों है।" कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

"Doctrine of basic structure is both necessary and desirable." Critically analyze the statement. (150 words) 10

'केशवानंद भारती' बनाम केरल राज्य (1973) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मूल संरचना का सिद्धान्त देकर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया जो संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुसार है।

मूल संरचना सिद्धान्त : आवश्यकता, वांछनीयता

→ (A) संविधान की मूल संरचना कोई तथ्य नहीं है अत: इसमें आत्मनिष्ठता व संवैधानिक गतिशीलता की व्यापक संभावना है।

जैसे - मूल संरचना का व्यापक विस्तार हुआ है, (पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, संघवाद)

(B) संविधानवाद की भावना के अनुसार है

(C) संसद की असीमित शक्तियों से संविधान में शक्ति संतुलन (चेक एंड बैलेंस) पर संकट

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

आ सकता है। जैसे- राष्ट्रीय आपातकाल में 42 संविधान संशोधन द्वारा न्यायालय की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास।

(v) अधिनायकवाद व बहुमत की तानाशाही को रोकने व न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बनाए रखने हेतु जरूरी।

(iv) विधायिका में लोकप्रिय बहुमत दल की सरकार होती है अत: न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा जैसे- 99वाँ संविधान संशोधन द्वारा NJAC को रद्द।

(v) मूल संरचना का सिद्धान्त संविधान में समय के साथ प्रगतिशीलता लाने में सहायक

जैसे- निजता का अधिकार

जैसे- चयन का अधिकार

जैसे- मूल अधिकार व DPSP में संतुलन (मिनर्वा मिल्स वाद 1980)

अत: मूल संरचना का सिद्धान्त न्यायपालिका को सही मायने में संविधान का संरक्षक व रक्षक बनाता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

3. भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता तथा भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों के संवर्द्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the significance of India's diaspora and its role in enhancing India's economic and strategic interests. (150 words) 10

विश्व बैंक के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस (प्रेषण) प्राप्त कर विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया जो भारतीय डायस्पोरा के कारण ही संभव रहा

भारतीय प्रवासी समुदाय : आर्थिक हित

(क) भारतीय प्रवासियों द्वारा देश में भेजे गए प्रेषण (111 बिलियन डॉलर) से भारत का भुगतान संतुलन (BoP) संतुलित होता

(ख) भारतीय उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी करते हैं। वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की माँग को बढ़ाते हैं जैसे - भारतीय खान-पान, मसाले, अचार

(ग) NRI's द्वारा BoP में डॉलर जमा द्वारा विनिमय दर को सहारा।

(घ) स्टार्टअप + अन्य तकनीकी कौशल पूर्ण रोजगार, प्रबंधन व बिजनेस व्यवहार को बढ़ाते हैं।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

(घ) भारत की IT और सॉफ्टवेयर इन्डस्ट्री को बढ़ावा देते है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय प्रवासी समुदाय : सामरिक हित

↳(क) भारतीय प्रधानमंत्री ने इन्हें सांस्कृतिक राजदूत (कल्चरल एम्बेसडर) की संज्ञा दी।

↳(ख) भारतीय सॉफ्ट पॉवर मैट्रिक्स में बड़ा योगदान देते है।
- भारतीय पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा
- योग, आयुर्वेद, संगीत, साहित्य
- भारतीय त्यौहारों को लोकप्रिय करना

↳(ग) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व असैन्य परमाणु समझौतें जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक नीतियों में दबाव समूह का कार्य करते है।

↳(घ) प्रवासी देशों की राजनीति में भारत की तरफ सकारात्मक रूख बनाते है - (कमला हैरिस - ऋषि सुनक)

अतः प्रवासी भारतीय भारत की अर्थव्यवस्था और सामरिक बढ़त के लिए पूंजी है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

4. "राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक अनूठा मंच है, जिसे देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को स्वतः संज्ञान में लेने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।" इस संदर्भ में राष्ट्र के पर्यावरण शासन में NGT के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

"National Green Tribunal (NGT) is a unique forum endowed with suo motu powers to take up environmental issues across the country." In this context analyse the importance of NGT for environmental governance of the nation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संविधान के अनुच्छेद - 243(B) के तहत केन्द्र सरकार ने पर्यावरणीय विवादों को तीव्र व अधिक विशेषज्ञता के साथ हल करने के लिए वर्ष 2010 में NGT की स्थापना की।

NGT की स्वतः संज्ञान शक्तियाँ

↳(क) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम -1986 के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी मामलों में NGT अति सक्रिय भूमिका निभाता है

↳(ख) (एम. सी. मेहता वाद (1986)) में सर्वोच्च न्याया. ने स्वच्छ पर्यावरण को अनु. 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना अतः प्रदूषण, पर्यावरण ह्रास और अवैध खनन मामलों में NGT का क्षेत्राधिकार अधिक व्यापक है।
- अरावली खनन वाद
- छत्तीसगढ़ अवैध माइनिंग वाद

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(ग) जुर्माना और क्षतिपूर्ति की शक्ति

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

पर्यावरण शासन में NGT का महत्व

↳ पर्यावरणीय विवादों में विधिक समझ व विशेषज्ञता की जरूरत होती है, जो कि परम्परागत न्यायप्रणाली में संभव नहीं

↳ NGT न्यायपालिका के अतिरिक्त बोझ को कम करता है।

↳ पर्यावरणीय मामलों में तीव्रता और प्रभावशीलता लाता है। eg- पटाखा फैक्ट्रियों का नियमन

↳ NGT में अधिक व्यावहारिक और समावेशी समाधान संभव होता है।

अतः NGT की भूमिका एक बेहतर पर्यावरण शासन के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें लंबित मामलों के निस्तारण हेतु आधारसंरचनात्मक क्षमता निर्माण समय की माँग है साथ ही तकनीकी समावेशन की भी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. भारत में न्यायिक सक्रियता का महत्त्वपूर्ण योगदान एक सुरक्षा वाल्व तथा यह विश्वास प्रदान करना है कि न्याय पहुँच से परे नहीं है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10
The great contribution of Judicial activism in India has been to provide a safety valve and a hope that justice is not beyond reach. Critically analyze the statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायपालिका की उस भूमिका से है जब सामान्य न्यायिक नियमों से आगे बढ़कर न्यायपालिका पूर्ण न्याय स्थापित करने व न्याय को सुलभ बनाने के लिए अपने क्षेत्राधिकार में रचनात्मक भूमिका निभाएँ। eg- 'विशाखा गाइडलाइन' (1997) द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु निर्देश देना।

eg- 'प्रकाश सिंह वाद' (2006) में पुलिस सुधार हेतु राज्यों को बाध्यकारी निर्देश

योगदान → (i) कार्यपालिका की उदासीनता व उपेक्षा के विरुद्ध उपाय का कार्य करती है।
eg- पटाखों पर रोक लगाना
eg- FCI के गोदाम में अतिरिक्त अनाज के वितरण गरीबों में करने का आदेश

www.dris…
Contact: 8750187501, 844…
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(ii) विधायिका की अनुपस्थिति व अभाव विधि के विकल्प के रूप में
ex- विशाखा गाइडलाइन

(iii) अनु. 39(A) निःशुल्क विधिक सहायता व न्याय तक पहुँच को सुनिश्चित करने

(iv) अनु. 142 पूर्ण न्याय को स्थापित करने
ex- अयोध्या राम मंदिर वाद में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देना

(v) नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु
ex- लॉकडाउन का नियमन करना
ex- दिल्ली वायु प्रदूषण मामले

लाभ → (A) न्याय तक पहुँच में वृद्धि
(B) जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास
(C) कार्यपालिका व विधायिका में सक्रियता, संवेदनशीलता
(D) परम्परागत न्याय प्रणाली - श्रमसाध्य, धनसाध्य

हालाँकि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमणवाद में संतुलन रखते हुए न्यायपालिका को दुर्लभ मामलों में ही इसका प्रयोग करना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. चुनावों के राज्य वित्तपोषण की अवधारणा से आप किस सीमा तक सहमत हैं? (150 शब्द) 10
To what extent do you agree with the concept of state financing of elections? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

17 वीं लोकसभा चुनाव में 10 हजार करोड़ से अधिक का खर्चा चुनावों को केवल अमीर लोगों का ही मँहगा शौक बना कर रखे हुआ है जिससे लोकतंत्र अमीरों का अमीरों के लिए शासन बनकर रह जाता है।

आवश्यकता → (i) अवैध कालाधन का प्रयोग चुनावों को धनबल का खेल बनाते हैं

(ii) मँहगे चुनाव → राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

(iii) वंचित वर्ग के लिए चुनावों में भागीदारी सीमित हो जाती है।

(iv) राजनीतिक न्याय में वोट देने के अधिकार में Right to elect का अधिकार भी है।

(v) चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भेदभावरहित निर्वाचन नहीं करवा पाता है।

(vi) मत व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- दिनेश गोस्वामी कमेटी (1990) ने भी प्रमुख राजनीतिक दलों को राज्य फंडिंग की बात कही

विपक्ष में तर्क - चुनाव में राज्य वित्तपोषण की सीमाएँ

(1) दूसरे देशों का अनुभव बताता है कि इससे चुनाव खर्च और बढ़ेगा न कि कम होगा

(2) अगंभीर उम्मीदवार और दल भी भाग लेंगे।

(3) राज्य के पास वित्त की वैसे ही कमी है।

लोककल्याण V/S चुनाव वित्तपोषण

(4) भारत में 2500 राजनीतिक दल है अतः वित्त का भारी बोझ असहनीय होगा।

(5) क्रियान्वयन में अनियमितता + कालाधन का संस्थागत प्रयोग बढ़ेगा

आगे की राह -> चुनाव आयोग ने नकद की जगह सुविधाएँ देने की बात कही है।

-> राज्य वित्तपोषण से अधिक चुनावी चंदे का विनियमन करना, इलेक्टोरल बॉण्ड में पारदर्शिता लाना, चुनावी खर्च की ऑडिट करना और राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने का प्रयास करना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेहिता को लागू करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण के लिये उपलब्ध विभिन्न विधायी समर्थनों पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द) 10

Social Audit is an important mechanism to enforce accountability and provide transparency in the administration. Highlight various legislative supports available for social audit in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सामाजिक अंकेक्षण से तात्पर्य सार्वजनिक कार्यों का अंकेक्षण जनता से करवाने की प्रक्रिया से है जैसे- 'मनरेगा' के कार्यों की ऑडिट ग्रामसभा द्वारा करना

सामाजिक अंकेक्षण : जवाबदेहिता : पारदर्शिता का तंत्र

* सामाजिक अंकेक्षण से प्रशासन में जनभागीदारिता बढ़ेगी -> पारदर्शिता (↑) -> जवाबदेहिता (↑)

* सामाजिक अंकेक्षण स्थानीय समस्याओं और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकता है

* प्रत्यक्ष जन भागीदारी प्रशासन में सक्रियता और रचनात्मकता को बढ़ा देगी
eg- तालाब निर्माण कार्य की साइट विज़िट करवाना
eg- शौचालय निर्माण का प्रत्यक्ष सामाजिक मूल्यांकन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(*) नौकरशाही → राजनीति के गठबंधन को तोड़कर भ्रष्टाचार की सम्भावना को कम करना eg- पंचायत स्तर पर ग्रामसभा

(*) कार्यों में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में सुधार होगा। औपचारिक खाना-पूर्ति की जगह जमीनी अवसंरचना का विकास

सामाजिक अंकेक्षण : भारत में विधायी समर्थन

↳ मनरेगा और पंचायती राज की योजनाओं में eg- मनरेगा एक्ट 2005 की धारा-7

↳ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल eg- NFSA-2013

आगे की राह → नागरिक चार्टर में शामिल करना और जागरूकता को बढ़ाना होगा

→ रचनात्मक सामाजिक अंकेक्षण [- महिलाओं के समूह - स्कूली बच्चों

→ आउटरीच कार्यक्रम और क्षमतानिर्माण कार्यक्रम

→ वित्त आडिटरों को सामाजिक अंकेक्षण से जोड़ना। अतः प्रशासन में जनता को बाहरी लाभार्थी समझने की बजाय भागीदार माना जाए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 भारत में सहकारी समितियों के संचालन में सुधार का उद्देश्य रखता है। इस संशोधन के महत्त्व पर बल देते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The proposed multi-state cooperative societies (Amendment) Bill 2022 seeks to revamp the operation of cooperative societies in India. Discuss the key provisions of the Bill, emphasizing the importance of this amendment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

9. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (150 शब्द) 10

Critically evaluate the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, that seeks to establish democracy at the grassroots. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

73 वें संविधान संशोधन अधि. 1992 द्वारा संविधान का भाग-9 जोड़ा गया व 11 वी अनुसूची में पंचायतों के 29 विषयों की सूची जोड़ी। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का व्यापक प्रयास है जिसमें आज 3 मिलियन जन प्रतिनिधि शामिल है।

उपलब्धियाँ -> (i) शक्तियों के विकेन्द्रीकरण द्वारा नागरिकों का सशक्तिकरण किया

(ii) पंचायती व्यवस्था द्वारा संविधान के अनु. 40 की भावना अनुसार स्थानीय स्वशासन को साकार किया (गांधी जी का स्वराज)

(iii) स्थानीय समस्याओं का स्थानीय संसाधनों से समाधान (ग्राम सशक्तिकरण)

(iv) राजनीतिक जागरूकता बढ़ी [वंचित वर्ग महिला

(v) महिला सशक्तिकरण बढ़ा आज 44.44 % स्थानीय प्रतिनिधि 10 महिलाएँ है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सीमाएँ → वित्तीय आत्मनिर्भरता नहीं है।
यु- मात्र 6% राजस्व ही स्वयं के स्रोत 94% के लिए राज्य केन्द्र पर निर्भर
↓
जिला प्रशासन से टकराव के कारण पंचायती व्यवस्था औपचारिकता मात्र बन कर रह गई
→ फंक्शनरीज का अभाव [सचिव के पद खाली - भवन संरचना जर्जर
→ जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का अभाव
→ स्थानीय स्तर पर जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति से मजबूत हुआ
→ प्रधान पति की समस्या (छद्म महिला सशक्तिकरण)
→ राज्य सरकारें विषयों का हस्तांतरण नहीं करतीं

आगे की राह → ई-पंचायत द्वारा तकनीकी समावेशन
→ नागपुर घोषणा पत्र द्वारा सशक्तिकरण
→ अवसंरचना विकास → स्वामित्व योजना
→ पंचायत सिटिजन चार्टर → आदर्श पंचायत योजना

पंचायतों को मानव संसाधन, वित्तीय तकनीकी एवं क्षमता निर्माण सहायता द्वारा सशक्त करके ही जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया जा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. जनगणना में होने वाली देरी से विकासात्मक पहलों की प्रभावशीलता और दक्षता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Delay in Population census has the potential to affect the efficacy and efficiency of developmental initiatives. Discuss. (150 words) 10

वर्ष 2011 की जनगणना के 10 वर्ष बाद वर्ष 2021 में 16वीं जनगणना होनी थी लेकिन दो वर्षों से लम्बित है; जिसका प्रभाव शासन में नीति-निर्माण और नीति-क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर पड़ेगा।

कारण → कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई
→ देश व्यापी लॉकडाउन में संभव नहीं।
→ इस जनगणना में पेपरलेस रिकॉर्ड की बात की जा रही है अतः मानव संसाधन व तकनीकी सहयोग की अधिक आवश्यकता।

प्रभाव – (i) जनगणना के डेटा योजना निर्माण में एक महत्वपूर्ण इनपुट का काम करता है जिसके अभाव में वास्तविक रियल टाइम आकांक्षाओं को समझने में बाधा उत्पन्न होगी।
(ii) जनगणना के आँकड़े अर्थव्यवस्था में

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

आधार डेटा का काम करते है।

(iii) स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी नागरिक केन्द्रित योजनाओं में जनसंख्या के डेटा से ही प्रगति मापी जाती है।

जैसे- साक्षरता बढ़ी या घटी?

जैसे- लिंगानुपात की वास्तविक स्थिति?

जैसे- मातृ मृत्युदर जैसे- जीवन प्रत्याशा?

(iv) 2021 जनगणना से ही 2026 में लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुर्नसीमन होना है अतः विलम्ब से पुर्नःसीमांकन में देरी होगी

आगे की राह --> देश की जनांकिकीय स्थिति को समझने के लिए जनगणना के आँकड़ों की विशेष जरूरत होती है। UNO के पोपुलेशन फंड के अनुसार भारत की आबादी 140 करोड़ हो गई है अतः इतनी बड़ी आबादी के डेमोग्राफिक डेटा के बिना प्रशासन कि विकासात्मक दक्षता को नहीं समझा जा सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में भारत-जापान सामरिक संबंधों में सहयोग के उभरते क्षेत्र और चुनौतियाँ क्या हैं? (250 शब्द) 15

In light of the changing geopolitical landscape, what are the emerging areas of cooperation and potential challenges in the India-Japan strategic relationship? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत और जापान पूर्व की दो पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और दोनों के मध्य बौद्धकाल से ही सांस्कृतिक संबंध रहे है।

सामरिक सहयोग के उभरते क्षेत्र

(क) मुक्त एवं खुला इन्डो-पैसेफिक क्षेत्र दोनों की ही रणनीतिक आवश्यकता है।
जैसे- क्वाड संगठन

(ख) हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को चीन की प्रभुता से मुक्त रखने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित परिवहन नौ प्रणाली के दोनों ही समर्थक है।

(ग) चीन की आक्रामकता के दोनों ही विरोधी है और दक्षिण चीन सागर और

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

पूर्वी चीन सागर में जापान के हितों की के प्रति भारत समर्थक की भूमिका में रहा

(ख) जापान की 'चाइना प्लस पॉलिसी' का भारत समर्थक रहा है और लाभार्थी भी

(ग) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक लचीला, विविध और विकेन्द्रीकृत बनाने की दोनों ही वकालत करते हैं।

(घ) चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए भारत जापान के साथ FTA और आसियान देशों के साथ अधिक केन्द्रित होना चाहता है।

साझा मंच → (i) क्वाड संगठन
(ii) मालाबार युद्ध अभ्यास
(iii) G20 (iiii) IPEF

जापान ने भारत में मेट्रो, सड़क और अन्य अवसंरचना में निवेश किया है।
जैसे- JICA द्वारा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

चुनौतियाँ → क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव
जैसे- डेट ट्रैप डिप्लोमेसी
चेक डिप्लोमेसी
जैसे- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव

→ दोनों देशों में व्यापार का आशानुरूप न रहना
→ जापान की USA पर अति निर्भरता
→ वैश्विक भू- राजनीतिक संकट और नई चुनौती
जैसे- रूस - यूक्रेन

आगे की राह → जापान और भारत एशिया की दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएँ हैं लेकिन द्विपक्षीय व्यापार को और बेहतर करने हेतु

→ कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना होगा।

→ क्वॉड का रचनात्मक उपयोग करना होगा
जापान को भारत में अधिक निवेश, और तकनीकी हस्तांतरण द्वारा चीन निर्भर आपूर्ति श्रृंखला को अधिक स्थिर और विविधिकृत करने का प्रयास करना चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

drishti दृष्टि The Vision

12. समकालीन वैश्विक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के महत्त्व का आकलन कीजिये तथा इसके सुधार और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Assess the significance of the United Nations in the contemporary world and discuss the need for its reform and revitalization. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध (1945) के बाद वैश्विक शांति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए की गई ताकि विश्व को एक और विश्व युद्ध का सामना न करना पड़े।

UNO का महत्व — उपलब्धियाँ

1. UNO ने अन्तर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दिया अपनी एजेंसियों के माध्यम से विश्व के लगभग हर क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ाने के प्रयास किए।

2. भू-राजनीतिक और मानवीय संकट में मानवता की सहायता की eg- इराक पर कुवैत का हमला
eg- आतंकवाद के खिलाफ युद्ध
eg- आपदा प्रबंधन
eg- Peacekeeping मिशन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

3. नियम आधारित विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दिया

4. कॉमन रिसोर्सेस के लिए संधियाँ की
eg- आउटर स्पेस ट्रीटी
eg- अंटार्कटिक ट्रीटी

5. परमाणु हथियारों का निःशस्त्रीकरण का प्रयास

6. अल्पविकसित व विकासशील देशों की आर्थिक सहायता eg-

7. शरणार्थियों व युद्ध बंदियों के लिए कार्य

8. वैश्विक महामारियों में सहयोग
eg- कोविड-19 महामारी (WHO की भूमिका)

सुधार की आवश्यकता → भारत के प्रधानमंत्री के अनुसार दुनिया बहुध्रुवीय की ओर बढ़ रही है ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अपने में सुधार करने की जरूरत है।
eg- UNO की UNSC में मात्र 5 देशों के पास वीटो पॉवर है जो वर्तमान शक्ति संतुलन का प्रतिबिंब नहीं करती है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

→ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में UNO में अफ्रीकी एवं एशियाई देशों को UNSC में शामिल कर इसे व्यापक प्रतिनिधित्व देना

→ UNO को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ताकि चीन व USA जैसे आर्थिक महाशक्तियों पर निर्भरता कम

→ UNO भू-राजनीतिक विवादों को सुलझाने में असफल
- यू- रूस-यूक्रेन
- यू- अफगानिस्तान
- यू- इजरायल - फिलिस्तीन

अतः इसे और सशक्त और समावेशी करना

→ जलवायु परिवर्तन जैसे ग्रहीय समस्याओं के समाधान हेतु अधिक शक्ति देना।

एक समावेशी और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने के लिए UNO में संगठन और विचार स्तर पर व्यापक सुधारों की जरूरत है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

13. उन कारकों एवं भू-राजनीतिक हितों पर चर्चा कीजिये जो मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को एक आकार प्रदान करते हैं। उन कदमों का भी उल्लेख कीजिये जिन्हें भारत को इस क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिये उठाने की आवश्यकता है। (250 शब्द) 15

Discuss factors and geopolitical interest which shapes India's engagement with central Asia. Also Mention steps which India need to take to enhance its reach in the region. (250 words) 15

'कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया' भारत की विदेश-नीति में मध्य एशिया के सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक महत्व को इंगित करता है।

'भारत : मध्य एशिया : संबंधों को आकार देने वाले कारक

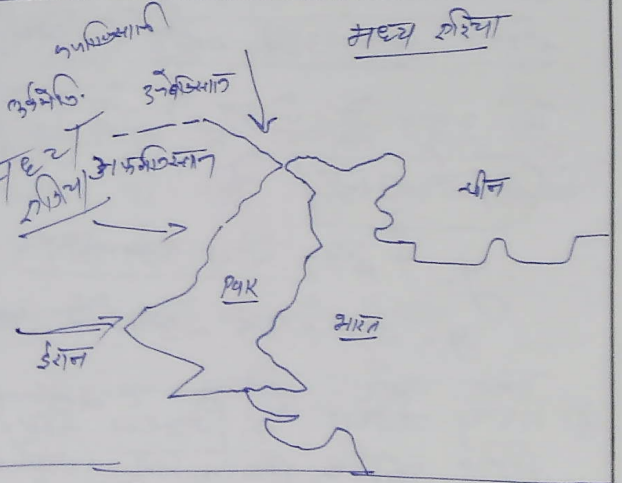

(1) साझा सांस्कृतिक इतिहास और जुड़ाव – भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान में मध्य एशिया का दुवार अफगानिस्तान भी शामिल है जिसका भारत से सांस्कृतिक संबंध है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

→ मध्य एशियाई फारसी, तुर्की और अफगान संस्कृति के कई तत्व भारतीय संस्कृति में शामिल हुए यु- सल्तनत काल
मुगल दरबारी संस्कृति
इन्डो इस्लामिक स्थापत्य

* भू-राजनीतिक हितों की बात करें तो मध्य-एशिया आर्क ऑफ एनर्जी (पश्चिमी एशिया) को भारत से जोड़ता है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है।
यु. TAPI गैस पाइपलाइन
यु- ईरान - पाक- इंडिया गैस पाइपलाइन

* मध्य एशिया में गोल्डन क्रैसेंट है जो अफीम की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी का गढ़ है। भारत में आंतरिक सुरक्षा और अवैध ड्रग तस्करी को रोकने के लिए SCO जैसे मध्य एशिया केन्द्रित संगठनों की जरूरत है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright - Drishti The Vision Foundation

* चीन -रूस - पाकिस्तान के मध्य बनते संबंधों को प्रति संतुलित करने हेतु जरूरी
* मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधनों पर चीन की बढ़ती रुचि भी एक कारण
* अफगानिस्तान में भारत का 3 B$ का निवेश की सुरक्षा और उसे जुड़ना।

भारत के प्रयास और आगे की राह

→ (क) अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से रिश्तों को सही करना होगा क्योंकि यह मध्य एशिया का द्वार है।
(ख) चाबहार बंदरगाह का तीव्र विकास
(ग) SCO मंच का सार्थक प्रयोग करना
(घ) अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को जल्द पूरा करना होगा।

मध्य एशिया से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए क्षेत्रीय संगठनों का प्रयोग करना यु- I2U2

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Copyright - Drishti The Vision Foundation

14. संविधान निर्माताओं ने भारत के लिये एक समान नागरिक संहिता की "आशा और अपेक्षा" की थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार क्या कदम उठा सकती है? (250 शब्द) 15

The founders of the Constitution had "hoped and expected" a Uniform Civil Code for India but there has been no attempt at framing one. In this regard discuss the need for a Uniform Civil Code in India and examine the challenges in its implementation. What steps can be taken by the government to overcome these challenges? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा। समान नागरिक संहिता से आशय सभी नागरिकों के लिए दिवानी और फौजदारी कानूनों को एक समान लागू करना

भारत में आपराधिक कानूनों का समान संहिताकरण किया जा चुका है। लेकिन दिवानी कानूनों की जगह अभी भी अलग-अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ है जैसे - हिन्दू कोड बिल-1955
- मुस्लिम पर्सनल लॉ

आवश्यकता - (i) संविधान के निर्माताओं की भावना समान नागरिक संहिता की थी

(ii) भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है अतः धर्म के आधार पर दिवानी कानूनों का विभाजन उचित नहीं है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

(iii) पर्सनल लॉ में महिलाओं को लेकर लैंगिक भेदभाव है जैसे - कुछ पर्सनल लॉ में बहुपत्नी प्रथा है।

(iv) नीति निर्देशक तत्व भविष्य के मौलिक अधिकार है। अतः समय आ गया है कि सार्वभौमिक समान नागरिक संहिता लागू हो

(v) गोआ में पहले से ही समान नागरिक संहिता है अतः अन्य राज्यों में भी लागू हो

(vi) धर्म में प्रगतिशीलता UCC के द्वारा

चुनौतियाँ → (i) अनु. 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार अतः न्यायिक वाद बढ़ेंगे

(ii) भारत में धर्म अभी भी समाज और नैतिकता में व्यक्तिगत न होकर सामूहिक मसला है।

(iii) मुद्दे के राजनीतिकरण से साम्प्रदायिकता बढ़ सकती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

(iii) विविधता भारत की खूबसूरती है अतः विविधता का संरक्षण राज्य का आश्रय है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

आगे की राह → (क) पर्सनल लॉ में प्रगतिशील सुधारवादी कदम उठाना

प्र- तीन तलाक को असंवैधानिक करना

प्र- मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति

(ख) समाज में आम सहमति बनाना व सुधार की मांग समाज द्वारा आए

(ग) राज्य द्वारा थोपी हुई समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय भावना को कमजोर करेगी

(ङ) लैंगिक भेदभाव को पर्सनल लॉ से हटाना

अतः समान नागरिक संहिता से पूर्व पर्सनल लॉ में सुधार के प्रयास हो और धर्मनिरपेक्ष चेतना के प्रयास को बढ़ावा दिया जाए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti दृष्टि The Vision

15. "भारतीय संसद एक संप्रभु विधायिका नहीं है; इसकी शक्तियाँ विशाल हैं लेकिन असीमित नहीं।" कथन पर टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The Indian Parliament is not a sovereign legislature; it has vast but not unlimited powers." Comment on the statement. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संविधान के अनु. 368 संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन वर्ष 1973 में केशवानन्द भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का सिद्धान्त देकर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया।

संसद की संविधान संशोधन की शक्ति

→ अनु. 368 में दो विधियां है

(A) विशेष बहुमत से दोनों सदनों में अलग-अलग विधेयक पारित कर

(B) सदन के विशेष बहुमत + आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन

सीमाएँ – अनु. 13 के अनुसार संसद मूल अधिकारों में कटौती करने वाली विधि नहीं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

बना सकती है। बनाती है तो असंगति की सीमा तक शून्य घोषित कर दी जायेगी।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ सज्जन सिंह वाद-1965 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनु. 13 के प्रावधान अनु. 368 पर लागू नहीं होते अतः संसद मूल अधिकारों में भी कटौती कर सकती है।

→ गोलकनाथ वाद-1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती फैसले को बदलते हुए कहा कि संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती अर्थात संसद की संशोधन शक्ति (अनु 368) सीमित है। असीमित नहीं।

→ केशवानन्द भारती वाद-1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना (Basic structure) को नहीं बदल सकती। मूल संरचना तय नहीं है इसे समय-समय के साथ न्यायपालिका

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

रेखांकित करेगी जैसे- लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और भी बहुत कुछ।

अतः संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान को पुनः लिख नहीं सकती है। अर्थात संविधान संशोधन शक्ति सीमित है।

——— + ———

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. वैश्वीकरण के युग में, विदेश नीति को आकार देने में पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा का महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ा है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपराष्ट्रीय अभिकर्त्ताओं की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है। भारत के संदर्भ में सविस्तार वर्णन कीजिये। (250 शब्द) 15

"In the era of globalization, the concept of Para diplomacy has become increasingly important in shaping foreign policy, highlighting the growing significance of subnational actors in international relations". Elaborate in the context of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

17. भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के उद्देश्य, लक्ष्यों और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Discuss the objective, goals and significance of India's National Geospatial policy. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. 'गरिमा मानव जीवन का सार है' और यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का लक्ष्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण में NHRC के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15

'Dignity is the essence of human life' and it is the objective of NHRC. Evaluate the performance of NHRC in preserving human rights. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Self Help Groups (SHGs) are the panacea for the socio-economic development of the country. Discuss the steps taken by the government to promote these groups.
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

20. विश्व के लिये ताइवान के सामरिक महत्त्व का आकलन करते हुए यह निर्धारित कीजिये कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी अवस्थिति और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक संभावित फ्लैशपॉइंट क्षेत्र के रूप में यह 21वीं सदी में शक्ति के भू-राजनीतिक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है? (250 शब्द) 15

Assess the strategic significance of Taiwan for the world, and how its position as a major economic power and a potential flashpoint in the Asia-Pacific region affects the geopolitical balance of power in the 21st century. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright Drishti The Vision Foundation